

उद्यमियों को उपयुक्त जमीन दिलाने में मदद करेगा प्रशासन

जासं, लखनऊ : लखनऊ में 32 हजार करोड़ की परियोजनाओं को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन कई हजार करोड़ के प्रोजेक्ट उपयुक्त जमीन नहीं मिलने के कारण लटके हैं। जमीन की वजह से रुके प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाने में अब प्रशासन मदद करेगा।

गत फरवरी में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में राजधानी में दो लाख करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव आए थे। इनमें कई निवेशक प्रोजेक्ट लगाने के इच्छुक तो हैं, लेकिन उनको उपयुक्त जमीन नहीं मिल पा रही है। कुछ समय पहले इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन ने भी इंडस्ट्री लायक जमीन नहीं मिलने की बात उठाई थी। उद्यमियों का कहना है जहां कनेक्टिविटी है वहां हर तरफ प्लाटिंग होने के कारण



32 हजार करोड़ की परियोजनाओं को मिल चुकी है हरी झंडी

जमीन की दरें इतनी महंगी हैं कि प्रोजेक्ट का बजट ही गड़बड़ा रहा है। प्रशासन को उद्यमियों को उचित दरों पर जमीन उपलब्ध करानी चाहिए। डीएम सूर्यपाल गंगवार का कहना है कि प्रदेश सरकार की जो नीति है उसके अनुसार मदद दी जा रही है। जिन निवेशकों को जमीन को लेकर समस्या है उनके साथ बैठक होगी और समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। उपायुक्त मनोज चौरसिया का कहना है कि प्लेज योजना के

हर क्षेत्र में बढ़ रहे अवसर

जीबीसी से उत्साह का संचार हुआ है। हर क्षेत्र में अवसर बढ़ रहे हैं। स्टार्टअप आ रहे हैं। एआइ की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। आने वाले समय में स्टार्टअप शुरू करने में आसानी होगी। फंड की व्यवस्था हो सकेगी। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में बहुत सारे नए स्टार्टअप के विषय में जानने का मौका मिला है।

—यश, स्टार्टअप फीडिंग ट्रेंड



तहत निवेशक दस से बीस एकड़ में औद्योगिक पार्क विकसित कर सकते हैं। सरकार प्रति एकड़ पार्क को विकसित करने के लिए एक

स्टार्टअप करना हुआ आसान

अपने स्टार्टअप के माध्यम से लखनऊ और आसपास के युवाओं को एआइ, डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स,

साफ्टवेयर ट्रेनिंग दे रहा हूं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में बहुत से युवाओं से मिलने का मौका मिला। लखनऊ में स्टार्टअप शुरू करने के लिए युवाओं को और अधिक सहूलियत मिलेगी।

—अमित श्रीवास्तव, स्कलेरा एआइ आधारित स्टार्टअप



प्रतिशत ब्याज पर ही लोन दे रही है। इस योजना का लाभ लेकर निवेशक जमीन की किल्लत दूर कर सकते हैं।